भारतीय संसद

PARLIAMENT OF INDIA

राज्य सभा सचिवालय

RAJYA SABHA SECRETARIAT

rajyasabhahindi.nic.in

Parliament House/Annexe,
New Delhi-110001
Website : http: / /rajyasabha.nic.in

No. RS. 18/1/2017- COSL

23rd May, 2017

From

Mahesh Tiwari
Director

To

Shri Haribhau Rathod, Ex-M.P. and MLC,
Banjar Hills, A-201, near Ashok Nagar Police Chowki,
Mulund (West) Mumbai-80.

Subject: Meeting of the Select Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017, as passed by the Lok Sabha.

Sir,

I am directed to state that the **Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017,** as passed by the Lok Sabha has been referred to a Select Committee of the Rajya Sabha on a motion adopted by the Rajya Sabha on 11th April, 2017 with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha. The Committee is, accordingly, examining the provisions of the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017.

2. The Committee headed by Shri Bhupender Yadav, M.P., has decided to invite organizations/experts on the Bill for a discussion on the provisions of the Bill. In this regard the Committee has desired to have your views on the said Bill.

3. In view of the above it is therefore, requested that you may kindly appear before the Committee to share your views on the proposed Legislation at **2.00 P.M. on Monday, the 5th June, 2017 in Room No. G - 074, Ground Floor, Parliament Library Building Parliament House Complex, New Delhi**. You are also requested to kindly submit your views in writing also for consideration of the Committee latest by 29th May, 2017.

4. An early confirmation shall be highly appreciated.

Yours faithfully,

(MAHESH TIWARI)
DIRECTOR
Ph: 23011973; 23034124
Email: mtiwari@sansad.nic.in

D - Branch 2088 5780 23/5

Scanned by CamScanner

हरिभाऊ राठोड
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

सत्यमेव जयते

Haribhau Rathod
(Ex. Member of Parliament)
Mobile: +91 99207 16999
A-201, Banjara Hills,
Near Ashok Nangar Police Station,
Mulund (W), Mumbai - 80.
E-mail: haribhaurathod@gmail.com
Website: www.haribhaurathod.com

26/5/2017

मान्यवर
श्री. भुपेन्द्र यादवजी
अध्यक्ष सिलेक्ट कमिटी सबऑर्डिनेट लेजिशलेशन
राज्यसभा.

विषय- संविधान (123 वा.संशोधन) बिल 2017

संदर्भ-आपका पत्र क्र.R.S. 18.01.2017 SOSL 23 MAY.2017

महोदय,

मै धन्यवाद देता हूँ, मुझे अपने उपरोक्त संशोधन बिल पर मेरे विचार रखने का अवसर प्रदान किया| **5 JUNE 2017** के बैठक में मै उपस्थित रहूँगा | और मेरे विचार कमिटी के समक्ष रखुंगा|

इस पत्र के साथ मै इस संदर्भ मे अपने विचार, लिखित सुझाव, और संविधान संशोधन के साथ भेज रहा हूँ| इसके कॉपीज निकाल के कमिटी के संबंधित सन्मानित सदस्योंको देने की कृपा करे|

धन्यवाद

आपका

हरिभाऊ राठोड
(पुर्व सासंद एवं विद्यमान MLA विधायक महाराष्ट्र)
Mob. - 9920716999

Email ID- haribhaurathod@gmail.com

श्री.हरिभाऊ राठोड,(पुर्व) सांसद एवं विद्यमान MLA महाराष्ट्र द्वारा संविधान मे संशोधन लाने हेतु (123 वा संशोधन) बिल 2017 के संदर्भ में विचार और सुझाव ।

संविधान (123 वा संशोधन) बिल 2017

इस बिल के उद्देश तथा कारणो के कथन में स्पष्ट किया गया है की,संविधान के तहत राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की स्थापना के बाद आयोगको संविधानात्मक दर्जा और अधिकार प्रदान किया जायेगा| इसी के साथ अन्य पिछडे वर्गो के सुचि मे समाविष्ठ करना और निकालना इसका अधिकार संसद को दिया गया|

सबसे पहले मै बताना चाहूँगा,कि संविधान अंतर्गत पिछडे वर्गो को अलग अलग नामों से जाना जाता है । जैसे की अन्य पिछडा वर्ग, सामाजिक और शिक्षा से पिछडा वर्ग, (Educationally and Socially Backward Class) नागरिकोंका पिछडा वर्ग| ऐसा लगता है कि संविधान जैसे महत्वपुर्ण दस्तऐवजो में भी एक जैसा नाम दिखाई नही देता और, इसलिए इन सभी नामों का एक प्रयोग जैसे की अन्य पिछडा वर्ग यही होना चाहिए । यही नाम सबसे प्रचलित है| इसलिए मेरा सुझाव है की संविधान मे संशोधन लाकर जहाँ जहाँ आवश्यक हैं वहाँ अन्य पिछडा वर्ग का ही प्रयोग करना चाहिये ।

जिन अन्य पिछडे वर्गो के लिए संविधानिक अधिकारों के साथ नया आयोग निर्माण करने का संशोधन ला रहे है यह सराहनिय है । इसे आयोग को अधिकार तो मिल जायेगा, लेकीन जिन अन्य पिछडे वर्गो के लिए हम आयोग का निर्माण कर रहे है , उन वर्गो को संविधानिक दर्जा संविधानिक सुरक्षा, अधिकार, शिक्षा और नोकरी मे समान अवसर प्रदान करने की, बात इस संशोधन बिल में दिखाई नही दे रही है ।

वैसा हि 342/(A) इस धारा के द्वारा संसद को दिए जा रहे अधिकारों मे केवल पिछडे वर्गो को संविधान के केंद्रिय अनुसुचि में सामील करने और हटाने का प्राविधान है| लेकीन राज्य सुची मे सामील करने का या हटाने का प्राविधान नही है| जहाँ तक कुछ ऐसी जातीयाँ है जो अलग नामों से जानी जाती है| और उन्हें अन्य पिछडे वर्गो में सम्मीलीत किया गया है| जैसे की विमुक्त घुमंतु समाज और अति पिछडा समाज । इन समाज को अनेक राज्य में नौकरी शिक्षा और प्रमोशन में अलग आरक्षण दिया गया है । इसमे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलगांना, कर्नाटक, हरियाणा,

झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और तामिलनाडू इन राज्यों मे अलग कॅटेगेरी (Category) बनाकर ओ.बी.सी को सब कॅटेगेरीयझेशन (Sub Categarization) किया गया है | और इसलिए यह संशोधन बिल 2017 अगर ऐसा हि पास हुआ , तो अतिपिछडो को संविधान के दायरेसे बाहर किया जायगा | इस लिए मेरे सुझाव को गौर से देखा जाये|

रिर्झवेशन (Reservation)के बारे मे सामाजिक न्याय और समानता लाना यह संविधान का मुलमंत्र है | और इसी उद्देश से संविधान में 16(4) अंतर्गत वर्ग या समुह ऐसा उल्लेख आया है| समुह का मतलब एक वर्ग, एकसमान सामाजिक स्थिती, जैसेकी विमुक्त घुमंतु समाज , परंपरागत व्यवसायी (Traditional Occupation) बलुतेदार,अतिपिछडा, किसानी, बागवानी करनेवाले जैसे समुह को सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करने का लक्ष रखा गया था | आजादी के बाद इस संदर्भ मे काफी चर्चा होती रही | लेकीन सफलता पुर्वक किसी भी सरकारने इसे देखा नही , बल्की अनदेखी की गयी | अब ऐसा लगता है एक सुनहरा मौका आया है , इस कमिटी के माध्यम से और सरकार से उम्मीद करते है की दबें कुचले अति पिछडो को सामाजिक न्याय मिलेगा| इस संदर्भ मे **(1)** श्री.आयंगार कमिटी (क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट इन्क्वायरी कमिटी 1949-50) **(2)** मंडल आयोग ने दि गयी श्री.एल आर नाईक इनकी डिसेन्ट नोट **(3)** उच्चतम न्यायालय इंद्रा सहयानी केस मे -1990 दि हुई ओ.बी.सी. सब कॅटेगेरीयझेशन का (Sub Categarization) सुझाव | **(4)** हाल ही मे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग के जस्टीस व्ही.ईश्वरय्या इनके द्वारा अन्य पिछडे वर्गों का सब कॅटेगेरीयझेशन (Sub Categarization) करने के सुझाव के साथ केंद्र सरकार को दि हुई रिपोर्ट (2 March 2015) इन सभी को देखते हुऐ, सामाजिक न्याय के अगली कडी मे एक अच्छा कदम , और इस विचारो के साथ संविधान के अनेक धाराओंमें संशोधन सुझा रहा हुँ | इन सभी संशोधनोको गंभीरता से देखा जाये | इसी मनोकामना के साथ कमिटी के समक्ष सुझाव समर्पित कर रहा हुँ |

धन्यवाद!

Amendment suggested by shri Haribhau Rathod Ex. MP and sitting MLC from Maharashtra, on the proposed legislation of the constitution (123rd Amendment)Bill, 2017 as passed by Loksabha and referred to Rajya sabha

1) In article 15 of the constitution in clause (4) for the words" any socially and educationally backward classes of citizens " The words "Other backward classes" be substituted .

2) In article 15 of the constitution clause (5) for the words "socially and educationally backward classes of citizens " the word "other backward classes " be substituted.

3) In article 16 of the constitution, in clause (4) for the word "any Backward class of citizens " the words "Other Backward Classes " be substituted.

4) In article 16 of the constitution in clause(4A) for the words "scheduled castes and scheduled Tribes" the words scheduled castes , scheduled Tribes and Other backward classes be substituted.

5) In article 46 on the constitution after the words "scheduled castes and scheduled Tribes " the words "Other backward classes " be substituted.

6) For article 335 of the constitution the following articles be substituted namely :-

335. Claims of scheduled castes, scheduled Tribes and other backward classes to services and posts :- The claims of the members of the scheduled castes, the scheduled Tribes ,and The Other backward classes shall be taken in to consideration ,consistently with the maintenance of

efficiency of administration ,in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or of a state .

Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the scheduled castes, the scheduled Tribes and the Other backward classes for relaxation in qualifying marks in any

examination or lowering the standard of evaluation,for reservation in matters or promotion to any class or classes of services of posts in connection with the affairs of the Union or of a state.

7) After article 342 of the constitution the following articles shall be interested namely :-

342 A (1).The President may with respect to any state Union territory and where it is a state after consultation with the Governor there of by public notification specialy categorization of the backward classes which or the group Within Other backward classes which Shall for the purposes of this constitution be deemed to be Other backward classes namely :-

A .Scheduled Denotified and NomadicTribes ,
B. Scheduled Most Backward classes,
C. Scheduled Traditionally Ocupational Community. And
D. Scheduled Farmers and Farming labor community In relation to that state or Union territory as the case may be .

2.Parliament may by law include in or exclude from the central and state list of Other Backward Classes specified in a notification issued under class (1)any Other Backward Classes or part of group within any scheduled Of A,B,C,and D with the classification within the Other Backward classes, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be veried by any subsequent notification.

8) In article 366 of the constitution after clause (26 B) ,the following clause shall be inserted ,namely :-

'(26 C) "Other Backward Classes means the backward classes as are classified are so deemed under article 342 A for the purposes of this constitution.